



बिहार में सुशासन बाबू युग का अंत? नीतीश ने दाखिल किया रास के लिए नामांकन, अमित शाह भर रहे साथ

पटना ०५/०३ (संवाददाता): बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार विधानसभा पहुंचे और अपना नामांकन पत्र जमा किया। कुमार वर्ष 2005 से अब तक रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नए मुख्यमंत्री और राज्य की नयी सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। कुमार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "दो दशकों से अधिक समय तक आपने मुझ पर लगातार भरोसा



और समर्थन जताया है। उसी विश्वास की ताकत से हमने बिहार और आप सभी की पूरी समर्पण भावना से सेवा की है। आपके भरोसे और समर्थन के कारण ही आज बिहार विकास और सज्जमान की एक नयी पहचान प्रस्तुत कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि अपने संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनकी इच्छा रही है कि वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों के सदस्य बनें। उन्होंने कहा, "इसी आकांक्षा के अनुरूप मैं इस बार होने वाले चुनाव में राज्यसभा

का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ।" कुमार ने कहा कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आश्रय देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी आपसे मेरा संबंध बना रहेगा और विकसित बिहार के निर्माण के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मेरा

संकल्प अटल रहेगा। राज्य में बनने वाली नयी सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में सच्चारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को प्रचंड जीत दिलाने के बाद कुमार के पद छोड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कोई नेता राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। यदि ऐसा होता है तो बिहार को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलेगा। हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अब तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। बिहार से राज्यसभा की पांच सीट के लिए 16 मार्च को मतदान होना है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बृहस्पतिवार है।

इनके दामन पर कोई दाग नहीं, स्वर्णिम अध्याय है नीतीश कुमार का कार्यकाल-अमित शाह

पटना ०५/०३ (संवाददाता): गुरुवार को बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला, जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नीतीश कुमार के अलावा, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन सहित अन्य एनडीए उम्मीदवारों ने भी उच्च सदन के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने दो दशकों से अधिक समय तक इस पद पर रहने के बाद राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और मौजूदा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 75 वर्षीय नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि नए मंत्रिमंडल को उनका पूरा समर्थन प्राप्त होगा। नामांकन के बाद अमित शाह ने कहा कि मैं नितिन नबीन, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और सुदेश राम के राज्यसभा नामांकन समारोह में शामिल होने पटना आया हूँ। नितिन नबीन ने राज्य में एक लंबे और सफल राजनीतिक करियर के बाद भाजपा के राष्ट्रीय



अध्यक्ष बने और अब राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही, लंबे अंतराल के बाद वे एक बार फिर राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली लौट रहे हैं। मैं और हमारे सभी एनडीए सहयोगी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बिहार की जनता द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा और सज्जमान दिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह घटनाक्रम नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यसभा में जाने की घोषणा के बाद सामने आया है।

नेतृत्व में 11 वर्षों तक उन्होंने बिहार की प्रगति में हर तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्हीं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सभी पहलें बिहार की जनता तक पहुंचीं। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली लौट रहे हैं। मैं और हमारे सभी एनडीए सहयोगी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बिहार की जनता द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा और सज्जमान दिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह घटनाक्रम नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यसभा में जाने की घोषणा के बाद सामने आया है।

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, तीन निलंबित विधायक भाजपा में शामिल

गुवाहाटी ०५/०३ (संवाददाता): असम कांग्रेस के तीन निलंबित विधायक कमलाज्या डे पुरकायस्थ, बसंत दास और शशि कांत दास शनिवार को गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में राज्य पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, खासकर पिछले महीने असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह के सच्चारूढ़ दल में शामिल होने के बाद।



में नयापन नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने मंगलवार को आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की।

पबित्रा मार्गेरिता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में कोई नयापन नहीं है। 42 उम्मीदवारों में से लगभग 20 को पिछले चुनावों में जनता ने कई बार नकार दिया था। हमें इससे कोई चिंता नहीं है। इससे पहले बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची की आलोचना करते हुए इसे वंशवादी सूची बताया और भाजपा द्वारा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर दिए जा रहे जोर की सराहना की। पत्रकारों

कांग्रेस की रास लिस्ट जारी, अभिषेक सिंघवी फिर तेलंगाना से उम्मीदवार

नयी दिल्ली ०५/०३ (संवाददाता): राज्यसभा चुनावों की सरगमी के बीच कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को अपने छह उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण सूची जारी कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें तेलंगाना से मैदान में उतारा है। इस सूची में छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के लिए भी नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस की से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। वह वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है। तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ



अधिवक्ता सिंघवी को अपने शासन वाले तेलंगाना से फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। सिंघवी वर्तमान में तेलंगाना से ही राज्यसभा सदस्य हैं। प्रदेश में दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने दूसरी सीट के लिए वी नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस की इस सूची से स्पष्ट है कि पार्टी राज्यसभा में अपनी %फायरपावर% (बौद्धिक और कानूनी क्षमता) को बनाए रखना चाहती है। अभिषेक सिंघवी जैसे वरिष्ठ नेता का फिर से सदन में जाना कांग्रेस के लिए विधायी चर्चाओं और कानूनी मोर्चों पर मजबूती प्रदान करेगा। वहीं, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेतृत्व को मौका देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की है।

दिल्ली में समय से पहले गर्मी की दस्तक! सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंचा पारा

नयी दिल्ली ०५/०३ (संवाददाता): राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 78 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एज्यूआई) 134 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य



से 50 के बीच एज्यूआई को 'अच्छ', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने और आसमान साफ रहने के कारण

आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा हो सकता है। दोपहर के समय धूप तेज रहने की संभावना है, जिससे गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि, मध्यम श्रेणी की हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक चिंताजनक नहीं है, लेकिन संवेदनशील लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

बंगाल में एसआईआर की जांच का डर, 48 घंटों में 3 लोगों ने आत्महत्या

कोलकाता ०५/०३ (संवाददाता): राज्य में पिछले 48 घंटों में एसआईआर के फैसले के साथे में आए तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक अन्य व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई, जिसके लिए परिवार ने एसआईआर से संबंधित चिंता को जिम्मेदार ठहराया है। मगरहाट के 44 वर्षीय वैन चालक रफीक अली गाजी ने कथित तौर पर मंगलवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जब उन्हें पता चला कि पिछले शनिवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम विचाराधीन के रूप में दर्ज है। रफीक की पत्नी अमीना

बीबी ने चुनाव आयोग के खिलाफ उस्ती पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया और बुधवार को कुछ समय के लिए उस्ती-शिराकोल सड़क को अवरुद्ध कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रफीक अली गाजी (44) का शव दक्षिण 24 परगना के धोलपारा इलाके में बुधवार सुबह अपने कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। उन्होंने कहा, गाजी का नाम सूची में विचाराधीन श्रेणी में पाया गया। उनके परिवार ने दावा किया कि उस श्रेणी में अपना नाम पाकर वह गंभीर

मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने कहा कि इससे पहले एक अन्य घटना में जलपाईगुड़ी शहर में मोमो विक्रंता गौरंगा डे (62) को भी मंगलवार सुबह अपने आवास के शौचालय में लटका हुआ पाया गया था। डे की मौत को अंतिम सूची में उनके नाम के गायब होने से जोड़ते हुए, सच्चारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को %एक्स% पर पोस्ट में कहा कि बंगाल में एक बार फिर दिल दहला देने वाली त्रासदी हुई। जलपाईगुड़ी में एक मामूली मोमो विक्रंता, गौरंगा डे ने लगभग चार दशकों के मतदान के बावजूद निर्वाचन आयोग के एसआईआर द्वारा उनका नाम हटा दिए जाने के बाद अपनी जान था।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का इस्तीफा, आर एन रवि होंगे नए राज्यपाल

कोलकाता ०५/०३ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को अचानक हलचल तब बढ़ गई जब राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने नई दिल्ली में अपना इस्तीफा सौंपा है। बताया जा रहा है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला लिया गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने राज्यपाल के पद पर पर्याप्त समय बिताया है। बता दें कि सी. वी. आनंद बोस की नवंबर 2022 में केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल का



राज्यपाल नियुक्त किया गया था और तब से वह इस पद पर कार्य कर रहे थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति भी सामने आती रही है। कई बार प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच विषय बयानबाजी भी चर्चा का विषय बनी रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम

पर प्रतिक्रिया दी है। मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि आर. एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की खबर से वह हैरान और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस्तीफे के पीछे के कारणों की

जानकारी नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन पर कुछ दबाव डाला गया हो। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर किसी राजनीतिक उद्देश्य से चुनाव से पहले ऐसा कदम उठाया गया है तो यह गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उन्हें पहले से कोई औपचारिक परामर्श नहीं दिया

गया। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार कई मामलों में राज्य सरकार से औपचारिक बातचीत या जानकारी साझा करने की परंपरा का पालन किया जाता रहा है। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के फैसले सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर सकते हैं और इससे राज्यों की गरिमा पर असर पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक परंपराओं का सज्जमान किया जाना चाहिए। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल पद में बदलाव का क्या असर राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है।

विविध समाचार

जो लोग चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भारत ने अपने अंदाज में सख्त जवाब दे दिया है

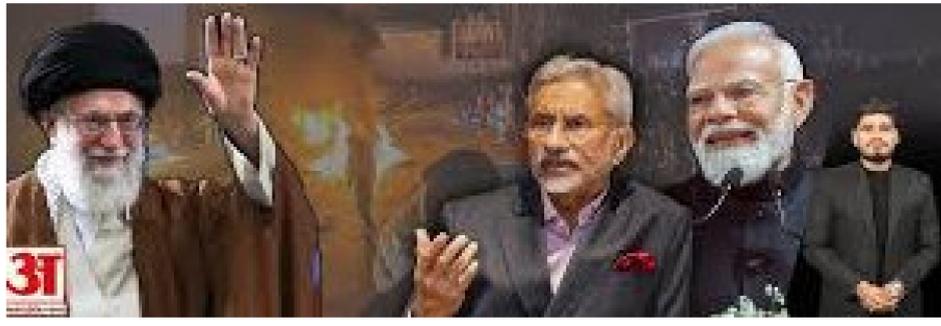
नयी दिल्ली 04/03 (संवाददाता): ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि भारत की प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आयी है? कई दिनों तक चली इस चर्चा के बीच भारत ने अपने अंदाज में इस सवाल का जवाब दे दिया है। हम आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी आज नयी दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास पहुंचे और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खामेनेई की मौत पर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की। इस कदम को भारत की औपचारिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

हम आपको बता दें कि खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान सरकार ने अपने सर्वोच्च नेता की कथित शहादत के सज्मान में चालीस दिन के सार्वजनिक शोक और सात दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। देश भर में धार्मिक सभाएं और स्मरण कार्यक्रम आयोजित किये जा

रहे हैं। इसी कड़ी में नयी दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिसरी पहुंचे थे।

उधर पश्चिम एशिया के कई शहरों में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। गुरुवार को दोहा और मनामा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गयीं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विस्फोट शहरों के केंद्रीय क्षेत्रों के करीब होते हुए महसूस किये गये। कुछ लोगों ने आकाश में गतिविधियां देखे जाने की भी सूचना दी, खासकर उन इलाकों के आसपास जहां पहले अमेरिका के दूतावास को खाली कराया गया था।

संयुक्त अरब अमीरात ने भी हमलों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। इसके अलावा कुल 129 ड्रोन का पता लगाया गया जिनमें से 121 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया जबकि आठ



देश की सीमा के भीतर गिर गये। मंत्रालय ने बताया कि ईरान की आक्रामक गतिविधियों की शुरुआत से अब तक संयुक्त अरब अमीरात की ओर कुल 189 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गयीं, जिनमें से 175 को नष्ट कर दिया गया, 13 समुद्र में गिरीं और एक मिसाइल देश की सीमा के भीतर आ गिरी। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक कुल 941 ड्रोन का पता लगाया गया जिनमें से 876 को रोक दिया गया जबकि 65 देश के भीतर गिरे। इसके अतिरिक्त 8 ज़रूज मिसाइलों का भी पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इन

हमलों के कारण कुछ स्थानों पर सीमित नुकसान हुआ और तीन लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मृतकों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 78 लोगों के घायल होने की सूचना है जिनमें अमीरात, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलिपीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अजरबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान और अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं।

अबू धाबी में एक और घटना सामने आयी जब वायु

रक्षा प्रणाली द्वारा रोके गये ड्रोन के मलबे गिरने से छह लोग घायल हो गये। यह मलबा अबू धाबी औद्योगिक नगर क्षेत्र के दो स्थानों पर गिरा। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था, लेकिन उसके टुकड़े गिरने से आसपास के क्षेत्रों में चोट लगने की घटनाएं हुईं।

क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए कतर ने भी सावधानी के कदम उठाये हैं। कतर के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अमेरिका के दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने

कहा कि यह केवल एहतियाती कदम है और प्रभावित लोगों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था की जा रही है।

उधर, इस संकट का असर हवाई यातायात पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अबू धाबी की विमान सेवा इतिहाद न घोषणा की है कि सुरक्षा कारणों से अबू धाबी से आने जाने वाली सभी निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें छह मार्च की सुबह तक स्थगित रहेंगी। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

वहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां बन गयी हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 13 देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने का निर्देश दिया है। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन भी शामिल हैं।

उधर, संकट के कारण बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। एक मार्च से अब तक 17 हजार से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार फंसे हुए लोगों के रहने और भोजन का खर्च भी वहन कर रही है।

इस बीच, व्यापारिक गतिविधियों पर भी इस संघर्ष का असर पड़ने लगा है। भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर पांच हजार से अधिक निर्यात कंटेनर अटक हुए हैं जिनमें लगभग एक हजार रॉफ़ेजरेटेड कंटेनर खराब होने वाली वस्तुओं से भरे हैं। आपूर्ति शृंखला पर पड़ रहे इस प्रभाव से वैश्विक व्यापार में भी चिंता बढ़ गयी है। इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। इतिहाद रेल ने अबू धाबी में यात्री रेल सेवाएं शुरू कर दी हैं ताकि सऊदी अरब में फंसे अमीराती नागरिकों को वापस लाया जा सके। यह सेवा सामान्य रूप से वर्ष के अंत में शुरू होने वाली थी, लेकिन वर्तमान संकट को देखते हुए इसे पहले ही शुरू कर दिया गया। विशेष यात्री रेल सेवाएं अल धफरा क्षेत्र के चुवैफात स्टेशन से अबू धाबी नगर के अल फया स्टेशन तक चलाई जा रही हैं। अब तक तीन विशेष रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं जिनके माध्यम से कई नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। उधर, दुबई से भारत लौटने वालों ने बताया है कि हालात बेहतर मगर चिंताजनक हैं। बहरहाल, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक कूटनीति, व्यापार और परिवहन व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं।

दिल्ली में जियोपॉलिटिक्स का महाकुंभ, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब होगें मुख्य अतिथि

नयी दिल्ली 04/03 (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है। तीन दिवसीय यह कार्यक्रम, जो 5 से 7 मार्च तक निर्धारित है, वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाएगा।

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और मुख्य भाषण देंगे। विश्व भर की सरकारों, विचारकों और रणनीतिक समुदायों की भागीदारी से आयोजित इस संवाद में 110 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे,



जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, संसद सदस्य, सैन्य कमांडर, व्यापारिक नेता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार और विद्वान शामिल हैं। इस वर्ष के आयोजन का विषय है संस्कार - अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति।

तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में छह मुख्य विषयों पर चर्चा होगी- विवादित सीमाएं, शक्ति, ध्रुवीकरण और परिधि; साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण- नए समूह, नए

संरक्षक, नए रास्ते; श्वेत व्हेल- एजेंडा 2030 की प्रगति; अंतिम क्षण- जलवायु, संघर्ष और विलंब की कीमत; भविष्य की दुनिया- एक तकनीकी-लोक की ओर, और टैरिफ के दौर में व्यापार- पुनर्गठन, लचीलापन और पुनर्निर्माण। लगभग 2,700 प्रतिभागियों के व्यक्तिगत रूप से संवाद में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि कार्यवाही का वैश्विक स्तर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और लाखों लोग इसे

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। ऑज्ज्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह तीन दिवसीय सम्मेलन 5 से 7 मार्च तक चलेगा और इसमें इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि तकनीकी व्यवधान, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार वैश्विक राजनीति को नया आकार दे रहे हैं।

इस संवाद में शामिल होने वाले कई गणमान्य व्यक्तियों में माल्टा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों एवं पर्यटन मंत्री इयान बॉर्ग; भूटान के विदेश मामलों एवं बाहरी व्यापार मंत्री ल्योपो डी एन धुंगेल; मॉरीशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतराष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफूल और सेशेल्स के विदेश मामलों एवं प्रवासी मामलों के

मंत्री बैरी फॉरे शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस सम्मेलन में शामिल होने वाले एक अन्य गणमान्य व्यक्ति श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेशी रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिथा हेरथ हैं। इस वर्ष की चर्चा पारंपरिक गठबंधनों और विश्लेषकों द्वारा वर्णित तकनीकी-ध्रुवीय दुनिया के बीच तनाव पर केंद्रित है, जहां प्रभाव तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाओं और डिजिटल अवसरचना पर नियंत्रण द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। संवाद का समापन भारत के दीर्घकालिक विकास रोडमैप पर चर्चा के साथ होगा, जिसमें अंकित भारत 2047 की परिकल्पना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता शताब्दी तक देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है।

खरगे का सरकार पर वार, बोले-नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति का सरेंडर कर दिया

नयी दिल्ली 04/03 (संवाददाता): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मध्य पूर्व संकट से निपटने के उनके तरीके को लेकर तीखा हमला करते हुए इसे भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों का घोर उल्लंघन बताया और प्रधानमंत्री पर भारत की विदेश नीति को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। एजस पर एक विस्तृत पोस्ट में, खरगे ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की दुर्दशा पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कई सवाल उठाए। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों का घोर उल्लंघन सबके सामने है।

खरगे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में आयोजित अंतराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से निहत्थे लौट रहा था, हिंद महासागर क्षेत्र में टॉरपीडो से हमला किया गया। इस पर कोई चिंता या संवेदना व्यक्त नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उन्होंने सरकार को अपनी ही नीतियों पर चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि महासागर नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के %शुद्ध सुरक्षा प्रदाता% होने की नीतियों पर हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं, जबकि आप अपने ही आंगन में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते? खरगे ने होर्मुज की खाड़ी में फंसे भारतीय नौसैनिकों के मानवीय संकट पर प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया कि होर्मुज की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले



आयोजित अंतराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से निहत्थे लौट रहा था, हिंद महासागर क्षेत्र में टॉरपीडो से हमला किया गया। इस पर कोई चिंता या संवेदना व्यक्त नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उन्होंने सरकार को अपनी ही नीतियों पर चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि महासागर नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के %शुद्ध सुरक्षा प्रदाता% होने की नीतियों पर हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं, जबकि आप अपने ही आंगन में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते? खरगे ने होर्मुज की खाड़ी में फंसे भारतीय नौसैनिकों के मानवीय संकट पर प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया कि होर्मुज की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले

38 वाणिज्यिक जहाज और 1100 नौसैनिक फंसे हुए हैं। कैप्टन आशीष कुमार समेत 2 भारतीय नौसैनिकों की कथित तौर पर मौत हो गई है। ऐसे में कोई समुद्री बचाव या राहत अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है?

उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक प्रभावों पर भी चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि कच्चे तेल और अन्य तेल का भंडार सिर्फ 25 दिनों का बचा है। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ, हमारी ऊर्जा संबंधी आपातकालीन योजना क्या है, खासकर तब जब भारत सरकार ने रूसी तेल का आयात रोकने की मांग को लगभग स्वीकार कर लिया है?

नीतीश के फैसले से जेडीयू में बगावत, रोते हुए समर्थक बोले- हम आपको जाने नहीं देंगे

पटना 04/03 (संवाददाता): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के फैसले से राज्य में नए मुख्यमंत्री का रास्ता खुल गया है, जिससे जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकर्ता और समर्थक हैरान हैं। पटना में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक जेडीयू कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हो सकता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया हो। एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

एक जेडीयू कार्यकर्ता ने कहा कि ये दुखद है। जो नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से लेकर आज तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे... बिहार की जनता उन्हें अपना परिवार मानती

है। नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई यहाँ मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम लोग रोए नहीं तो क्या करें? लाठी खाकर, लात खाकर हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, 2025 में हमने नीतीश कुमार के नाम पर घर-घर जाकर वोट मांगें। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो बिहार के लोग कहां जाएंगे? आज ही आप चुनाव करवा लें और जिसे मुख्यमंत्री बनाना है बना लें... कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि निशांत (नीतीश कुमार के बेटे) को राज्यसभा भेजें।

उन्होंने कहा कि यदि किसी को मुख्यमंत्री बदलने की इच्छा है, उन्हें लगता है कि उनमें नेतृत्व बदलने की ताकत है, उनके चेहरे में इतनी ताकत है तो वे चुनाव करवा लें और बहुमत ले लें हम कुछ नहीं कहेंगे... हम लोग यहां पर रहेंगे और उन्हें (नीतीश कुमार) नामांकन भरने के लिए नहीं जाने देंगे।

रास सीट न मिलने पर छलका आनंद शर्मा का दर्द, बोले-आत्मसम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है

नयी दिल्ली 04/03 (संवाददाता): कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने गुरुवार को कहा कि राजनीति में आत्मसम्मान बहुत महंगा होता है और सच बोलना अब अपराध माना जाता है। यह बयान उन्होंने तब दिया जब पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना उम्मीदवार नामित किया। दिल्ली रवाना होने से पहले शिमला में एएनआई से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी उम्मीदवार के रूप में ज्यों नहीं चुना गया, इस पर टिप्पणी करने की उनकी कोई संभावना नहीं है।

आनंद शर्मा ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं निराश हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा- राजनीति में आत्मसम्मान बहुत महंगा होता है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और सच बोलना अब अपराध माना जाता है। पार्टी नेतृत्व के फैसले का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि इसका जवाब केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने यह फैसला



लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ज्यों नहीं भेजा गया और आखिरी समय में उम्मीदवारी वापस ज्यों ली गई, इसका जवाब केवल वही लोग दे सकते हैं जो फैसले लेते हैं और जिनकी सलाह पर फैसले लिए जाते हैं। इस पर टिप्पणी करने की मेरी कोई संभावना नहीं है।

शर्मा ने कहा कि जो कुछ हुआ है, उससे मैं डरता नहीं हूँ। निर्णय लेने वालों के पास सर्वोच्च कमान का अधिकार है। शायद उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से यह निर्णय लिया है। वे इसके गुण-दोषों को समझ सकते हैं। जो कुछ हुआ है, मैं उसे समझा नहीं सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह निर्णय पार्टी नेतृत्व की

सिफारिश पर लिया गया था, तो शर्मा ने कहा कि वर्षों से हिमाचल प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सौभाग्य की बात रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिमला और हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा और मंडी सहित कई संस्थानों ने समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यह हिमाचलियों के लिए एक यादगार रहेगा। शर्मा ने कहा कि राज्य से उनका गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव है और वे यहाँ आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेरा घर है। मैं यहाँ आता रहता हूँ। मेरा पैतृक घर यहाँ है, और मैं आता रहूँगा। मैं हमेशा हिमाचल के लोगों के साथ रहूँगा।

रूह कंपा देने वाली वारदात! होली पर रंग डालने से नाराज दादी ने 4 साल के पोते पर उड़ेल दिया उबलता पानी

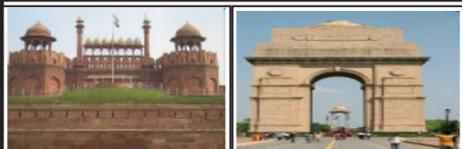
नागपुर 04/03 (संवाददाता): महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। होली की खुशियों के बीच एक चार साल के मासूम को अपनी ही सगी दादी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने त्योहार के उत्साह में अपनी दादी पर रंगीन पानी डाल दिया, जिससे नाराज होकर महिला ने बच्चे पर उबलता हुआ पानी उड़ेल दिया। छद्म फुटेज में दिख रहा है कि लड़का खेलने के लिए सिंधु ठाकरे नाम की महिला पर पानी छिड़कने की कोशिश कर रहा था, जो गर्म पानी की बाल्टी लेकर जा रही थी। बच्चे की हरकतों से गुस्सा होकर, उसने कथित तौर पर पूरी बाल्टी उस पर डाल दी।

वीडियो में बच्चा दर्द से तड़पता हुआ दिख रहा है। पास खड़ी एक और महिला को लड़के को टंडा करने की कोशिश में उस पर नॉर्मल पानी डालते हुए देखा गया, लेकिन वह कमर के नीचे 45 परसेंट जल गया। न्यूज एजेंसी इंडिया ने बताया कि बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस ने महिला के खिलाफ

केस दर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई (इंडिया) की रिपोर्ट के मुताबिक, नागपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी महिला सिंधु ठाकरे को खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
 PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
 FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
 AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
 ROURKELA, PH. 0661-2646999
 PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
 E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार



बच्चों में बढ़ रहा अकेलापन

मस्ती में दिन गुजारने वाली छुट्टियाँ अतीत की बात हो गईं। आज का बच्चा तो रवों की रेस का घोड़ा है जो हर दम जुलु हुआ है। उसकी दलगा अभिभावकों, शिक्षकों और उन शिक्षार्थियों के हाथ में है जिन्होंने आज के बच्चों की जिंदगी में छुट्टी का पीरियड ही नहीं बनाया। बच्चे अपने दोस्त और सहयोगियों पहले भी बनाते थे और अब भी बनाते हैं। आज भी उनका कोई एक मित्र होता है जो पनिह मित्र होता है या दो-तीन मित्रों का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे को समझते, जानते, चाहते हैं। मगर पढ़ाई का बोझ, कुछ कर गुजरने और शीर्ष पर रहने की अपेक्षाओं का बोझ दोस्तों से इनकी भावनात्मक निकटता को फलने-फूलने का समय नहीं देता। इनका समय एक दूसरे से नोटस का आदान-प्रदान करने में जितना जाता है उतना समय वे एक-दूसरे से मन की बात करने में नहीं निकाल पाते। संयुक्त परिवार टूट गए हैं। अब घर पर भी बच्चे समूह में नहीं रहते। पिछले बीस वर्षों में जमाना इतना बदला है कि अपसर पढ़े-लिखे माता-पिता का भी अपने बच्चों से स्पष्ट जनरेशन गैप होता है। अतः किशोर माता-पिता से मन की बात नहीं कह पाते। उन्हें पता है कि वे और माता-पिता संस्कारों के दो अलग छोरों पर खड़े हैं अतः उन्होंने मन की बात कह भी दें तो मा-बाप पक्का नहीं पाएंगे। आज के किशोरों की दोस्ती वरुणल माध्यम पर भी चलती रहती है। बच्चे पर अच्छी प्रोफाइल बनाने और अच्छा स्टेटस डालने का भी दबाव रहता है। आज का बच्चा 'वीयर प्रेशर' में ही बहुत से काम करता है। उसे दोस्तों को दिखाना, मा-बाप की अपेक्षाएं पूरी करनी हैं, उपभोक्ता संस्कृति के अनुरूप जीवन जीना है। आज बचपन और किशोरावस्था जटिलताओं से भर गए हैं। निहाय हर दूसरे-तीसरे दिन किसी किशोर अथवा किशोरी द्वारा आत्महत्या कर लेने की खबरें आती हैं। ये खबरें बाकी माता-पिता, शिक्षकों और समाज के लिए खतरों की घंटी होना चाहिए ताकि वे यह सोचें कि बच्चों के लिए कैरियर के जितनी ही महत्वपूर्ण परिवार से मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा, प्यार और हर हाल में अपनाए जाने का विधास भी है। कभी भी बच्चों को यह ताने नहीं मिलना चाहिए कि देखो हम तुम्हारे लिए किटना करते हैं और तुम हो कि अच्छा रिजल्ट नहीं लाते। बच्चों को बार-बार यह एहसास दिखाना उनमें स्वानि भाव पैदा करता है और जो अंततः अवसाद में भी परिणत हो सकता है।



आर्थिक प्रबंधन में रखें पूरी भागीदारी

बदलते वक्त के साथ अब महिलाओं को आर्थिक प्रबंधन में भी पूरी भागीदारी रखनी चाहिए। गृहिणी हो या कामकाजी, दोनों ही स्थितियों में यह जरूरी है कि स्त्रियां अपने वित्तीय पक्ष को मजबूत करें।

खुद को जानकार बनाएं
सबसे पहले वित्तीय फैसलों में अपनी जानकारी बढ़ाएं। वित्त संबंधी किताबों, खबरों और ऑनलाइन विशेषज्ञों की मदद से जानकारी इकट्ठी करें।

बजट प्रबंधन में भाग लें
परिजनों के मध्य आर्थिक और वित्तीय पहलुओं की चर्चा में शामिल रहें। बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी-विवाह और घरलू व्यय आदि, ये कुछ ऐसे बड़े खर्च हैं, जिनके लिए धन जुटाने के लिए आपकी भी सहमति और सहयोग आवश्यक है। ध्यान रखें कि चर्चा से आप बेहतर विकल्प खोज सकती हैं और आर्थिक आपदा को भी लाभ के अवसर में बदल सकती हैं।

बजट बनाएं, अमल करें
वित्तीय प्रबंधन की पहली सीढ़ी है, अपने आय-व्यय का ब्योरा रखना अर्थात् बजट बनाना। बजट बनाने के बाद उस पर अमल करना भी जरूरी है। एक कहावत है कि 'तेरे पांव पसारिए, जैती लांबी सौर' अर्थात् आय के अनुसार ही खर्चों को सीमित करें। यदि अतिरिक्त खर्च अपरिहार्य हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए सुलभ विकल्पों पर विचार करें।



आकस्मिक कोष बनाएं
मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। अनपेक्षित आने वाले खर्चों के लिए एक आकस्मिक कोष का निर्माण करें। इससे आप कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगी। इसके लिए एकमुश्त अथवा धीरे-धीरे धन जमा करें और उसे एक अलग बैंक खाते में रखें।

बचत भी आय है
कई गृहिणियां यह कहती हैं कि उनकी कोई आय नहीं है। वास्तव में बचत भी आय का एक स्वरूप है। छोटी-छोटी बचत लंबे समय में एक अच्छा कोष एकत्र करने में आपकी मदद कर सकती है।



भूख लगने पर शिशु देता है कुछ ऐसे संकेत

शिशु बोलकर आपको अपनी बात या जरूरत नहीं समझा सकता है इसलिए इतने छोटे बच्चों की बात आपको ही समझनी पड़ती है। बड़े बच्चों को जब भी भूख लगती है, वो बोलकर आपको बता देते हैं लेकिन नन्हे शिशु की बात और जरूरत को समझना मुश्किल होता है क्योंकि ये शिफ्ट रोककर ही अपनी बात कहते हैं और अभी इन्होंने बोलना शुरू नहीं किया होता है। नवजात शिशु बोलकर अपनी बात नहीं कर सकता है लेकिन वो कुछ संकेतों की मदद से आपको अपनी जरूरत के बारे में जरूर बताता है। अब आपको इसकी बात समझनी होगी।

शिशु से मिलने वाले कॉमन साइन
अगर बच्चा जगा हुआ है और एल्टं दिख रहा है, तो यह इस बात का साफ संकेत है कि उसे भूख लगी है। आपकी उदरगणना पाने के लिए शिशु अपने शरीर को हिलाता है। वो अपने पैर और हाथ इधर-उधर मारेगा।

पहली बार पैरेंट बने
अगर आप पहली बार पैरेंट बने हैं, तो शिशु की भाषा को समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में आपको इसमें दिक्कत हो सकती

है लेकिन धीरे-धीरे आप सब सीख जाएंगे। शिशु की बात समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि बच्चे को कब भूख लगी है। अगर आपको बच्चा यहां बताए गए कुछ संकेत दे रहा है, तो समझ लें कि उसे भूख लगी है।

कैसे समझें शिशु के संकेत
यदि शिशु लगातार अपनी उंगलियों को मुँह में ले रहा है, तो समझ लें कि उसे दूध पीना है। जब बच्चे को बहुत तेज भूख लगती है, तब वो अपना सिर हिलाने लगता है। बेचैन होने पर बच्चा मुँह भी बनाने लगता है। तेज सँ रोने का भी यही मतलब है कि शिशु को भूख लगी है। भूख लगने का यह सबसे स्पष्ट संकेत होता है।

दूध पीने के बाद भी रोए तो
नन्हा शिशु रोककर ही अपनी बात कहता है और भूख लगने का सबसे स्पष्ट संकेत भी वो रोककर ही देता है लेकिन कई बार शिशु के रोने की कोई और वजह भी हो सकती है। अगर दूध पीने के बाद भी बच्चा रो रहा है, तो इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। कई शिशु दूध पीने के बाद सोना चाहते हैं इसलिए दूध पिलाने के बाद बच्चे को सुलाने की कोशिश करें।

शिशु के रोने के कारण
आमतौर पर शिशु दिन में सबसे ज्यादा बार भूख लगने पर ही रोता है। वो रोककर आपको यह बताने की कोशिश करता है कि उसे भूख लगी है और दूध पीना है। लेकिन हर बार या हर रोज शिशु भूख की वजह से ही रो रहा है, ये जरूरी नहीं है। पेट दर्द या गैस की वजह से भी शिशु रो सकता है। कई घंटों तक शिशु के रोने की वजह कॉलिक पेन भी हो सकता है। अगर आपको शिशु के रोने की वजह समझ नहीं आ रही है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें।

डॉक्टर को कब दिखाएं
अगर बच्चा कुछ दिनों से लगातार रोककर भूख लगने का संकेत दे रहा है, तो आपको एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए। वही अगर शिशु को बहुत ज्यादा नींद आ रही है या दूध पिलाने के लिए हर समय आपको उसे उठाना पड़ता है, तो भी आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए।

स्टेनलेस स्टील से जंग हटाने के लिए अपनाएं यह आसान टिप्स

स्टेनलेस स्टील, एक ऐसा मैटेरियल है, जिसका लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। आपको अपने घर की किचन में ही स्टेनलेस स्टील के कई प्रॉडक्ट्स देखने को मिलेंगे और यह केवल बर्तनों तक ही सीमित नहीं है। न केवल रसोई में, बल्कि स्टेनलेस स्टील के कई अन्य महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं जैसे कि इसे पानी के नल, कृषि उपकरण और कई चीजों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के व्यापक उपयोग का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इसमें न केवल तागत कम आती है, बल्कि यह जंग के लिए भी प्रतिरोधी है। दरअसल, इसकी सतह पर एक क्रोमियम फिल्म होती है, जिसके

कारण यह जंग प्रतिरोधी है। यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद भी चमकदार रहता है। लेकिन जैसे ही यह क्रोमियम फिल्म स्टेनलेस स्टील की सतह से हटती है, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो विलिए आज हम यहां आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनके जरिए आप स्टेनलेस स्टील से जंग हटा सकते हैं-

बैकिंग सोडा का इस्तेमाल
बैकिंग सोडा की मदद से स्टेनलेस स्टील से जंग बेहद आसानी से हटाया जा सकता है। हालांकि इस तरीके को अपनाकर आप छोट्टे हिस्से से जंग को

हटा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच बैकिंग सोडा 2 कप पानी, एक चम्मच सफाई कपड़ा और एक ट्यूबला की आवश्यकता होगी। इस तरीके को अपनाकर आप सबसे पहले 1 चम्मच बैकिंग सोडा को एक कप पानी में मिलाएं। अब ट्यूबला की मदद से, जंग से प्रभावित हिस्से को रगड़ें। बैकिंग सोडा को नॉन-स्क्रिब होने के लिए जाना जाता है और इसलिए यह स्टील की सतह से जंग को धीरे से हटा देगा। एक बार जब जंग के दाग साफ हो जाएं तो आप इसे सामान्य पानी से धो सकते हैं और फिर कपड़े की मदद से इसे पोंछें। वही अगर एक बड़ा हिस्सा जंग से प्रभावित है तो यह स्टेप्स आपके काम नहीं आएंगे, बल्कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। इसके लिए आप सबसे पहले सतह को धोएं जैसे कि स्टेनलेस स्टील से बने बड़े कंटेनर को सबसे पहले धोएं करें। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी प्रकार के पदार्थ को इससे हटाते हैं। अब स्टेनलेस स्टील उत्पाद के प्रभावित क्षेत्र पर कुछ बैकिंग सोडा छिड़कें। सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिया बैकिंग सोडा के साथ कवर किया गया है। अब इसे 25-30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। अब



आपको बैकिंग सोडा वाले क्षेत्र को रगड़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप एक पुराने ट्यूबला का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि आपको बहुत अधिक आक्रामकता से नहीं, बल्कि धीरे से रगड़ना है। जब आप स्टील की सतह को छोट्टे हुए जंग को देखते हैं, तो आप इसे सामान्य पानी से धो दें। अंत में, इसे एक सूती कपड़े से पोंछ लें।

सिरका का इस्तेमाल
यह एक और तरीका है जिसके द्वारा आप स्टेनलेस स्टील से जंग हटा सकते हैं। आपको बस इतना करना होगा कि प्रभावित जगह पर सिरका लगाएं और इसे सूखने दें। फिर आप ट्यूबला की मदद से इस क्षेत्र को धीरे से साफ कर सकते हैं। इसके बाद, आप सतह को सामान्य पानी से धो सकते हैं और कपड़े की मदद से इसे पोंछ सकते हैं। आप देखेंगे कि जंग पूरी तरह से साफ हो गया है।



बचपन से सही हों खानपान की आदतें

बच्चों की खानपान की आदतें अब कम्बोबेठा हर घर में वित्ता का विषय बनती जा रही है। बार-बार कहने पर भी फल-सब्जियां ना खाना और जंक फूड खाने की जिद करना आजकल आम है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी यह जिद और खाने की चीजों को लेकर किया जाने वाला घुनाव ज्यादा अजीबो-नारीब होता जाता है। अभिभावक वित्त तो करते हैं पर एक समय के बाद वे चाहकर भी बच्चों की खानपान की आदतें नहीं सुधार सकते। नतीजा यह होता है कि वे छोटी-छोटी आदतें आगे चलकर बीमारी की बुनियाद बन जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि वे समय रहते पेटें। बचपन से ही खानपान की आदतों पर ध्यान दें ताकि आगे चलकर बच्चों की सेहत को नुकसान ना पहुंचे।

सही पोषण के बारे में बताएं
आजकल बच्चे जबरदस्ती थोपे जाने से कोई काम नहीं करते। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को जो कुछ भी करने को कहें उस काम के फायदे भी समझाएं। धीरे-धीरे और सुझाव के साथ उन्हें सही पोषण के बारे में बताएं। साथ ही खाने-पीने की अस्वस्थ आदतों को लेकर होने वाले नुकसानों की भी जानकारी दें। यह वित्त का विषय है कि आजकल कम उम्र में ही बच्चों को कई बीमारियां घेर रही हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह अस्वस्थ जीवनशैली ही है। इस अजब- गजब लाइफस्टाइल में खानपान की विगड़ी आदतें सबसे ऊपर हैं। इसलिए बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए उन्हें सही पोषण वाला खाना खाने के लिए समझाइए।

बच्चों को स्नेक अटैक जैसी आदतों से बचाएं। जो आजकल आम हो चली है। छोटी उम्र में ही उन्हें सही और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद खाने के बारे में जानकारी देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बचपन में जो स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों को घेर लेती हैं वे जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। इनमें मोटापे जैसी तत्कालीन सबसे ऊपर है। अध्ययन बताते हैं कि बचपन में मोटे रहे लोगों में से 50 से 80 फीसदी बड़े होने पर भी मोटापे के शिकार रहते हैं। ध्यान रहे कि उस कोई भी हो मोटापे अपने आप में कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है। हाल ही में आ रही सभी रिपोर्ट्स कम्बोबेश यही बताती हैं कि दुनिया भर में मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चे खासतौर पर बढ़ते वजन की समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर है, इस वजह से कम उम्र में ही सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियां भी बढ़ रही हैं।

कीजिए सेहत के खतरों का जिद
बच्चे खुद अपने स्वास्थ्य और सेहत के लिए सजग नहीं हो सकते। ना ही वे खान-पान की गलत आदतों के खतरों को समझ सकते हैं। उनका मासूम मन केवल स्वाद जानता है। इसलिए उन्हें सेहत के लिए खतरा पैदा करने वाली इस राह पर चलने से रोकने का काम मम्मी-पापा को ही करना होता है। इसके लिए आप उन्हें जंक फूड से होने वाले नुकसान प्यार से समझाएं। अगर उन्हें बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है तो घर में ही स्वाद का बदलाव कर कुछ अच्छा बनाकर खिलाएं और घर के खाने के फायदे भी बताएं। उन्हें समझाएं कि घर में बनाया गया खाना साफ-सुधरा और पीछेकहोता है जिसके कई सारे लाभ हैं। इसका एक फायदा यह है कि बच्चों में ऐसी आदतों के जड़ें जमाने से पहले ही वे उनसे बाहर आ

जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि खाने की आदतें बच्चों के व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं बिगड़ता खानपान अनियमित दिनचर्या की भी एक बड़ी वजह बनता है। परिणामस्वरूप छोटे-छोटे बच्चों में भी आजकल डायबिटीज जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इस तरह की आदतों का असर कई बार मोटापे या बच्चे के वजन कम होने के रूप में भी सामने आता है। खानपान की आदतें घर परिवार के माहौल के मूलाधिक भी बनती हैं। इसलिए पहले घर के बड़े अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाएं।

हमेशा मनमानी ना करने दें
खानपान की आदतें स्वाद के साथ ही सेहत भी लिए हैं, यह जरूरी है। इसलिए मनवाहा खाने की जिद करने वाले बच्चों को हर बार मनमानी ना करने दें। यदि आप घर में ही प्रोसेसड फूड लेकर नहीं आएंगे तो बच्चे कम से कम घर में तो बचे ही रहेंगे। बच्चों के खाने की चीजों में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करें। हमेशा बच्चों की मनमानी को मान लेना सेहत ही नहीं बिगड़ता बल्कि व्यवहार को भी उदा बनाता है। कई बार देखने आता है कि कुछ बच्चे खाना नहीं खाने के लिए भी जिद करते हैं। समय रहते सचेत होना जरूरी है क्योंकि ऐसी आदतें आगे चलकर बच्चों के जीवन पर बुरा असर डालती हैं। यह वित्त का विषय है कि आज दुनियाभर में 10 प्रतिशत बच्चे ओवरवेट हैं। हमारे यहां भी ये आकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं।

कलिंग समाचार



संपादकीय

शुक्रवार 06 मार्च 2026

कॉम्प्रोमाइज़्ड कौन है

पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, कांग्रेस का ये नया सूत्रवाक्य इस समय मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। राहुल गांधी ने ये बात संसद में कही, इसके बाद इसी वाक्य वाले टी शर्ट्स के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भोपाल में किसान महापंचायत में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का सच बताते हुए भी यही वाक्य कहा और किसानों को बताया कि कैसे उनके भविष्य को खतरे में डालकर नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के लिए घाटे का सौदा किया है। कॉम्प्रोमाइज़्ड शब्द का असर इतना गहरा हुआ कि अब भाजपा ने भी इसी का इस्तेमाल गांधी परिवार पर हमला करने के लिए किया। बुधवार को पीयूष गोयल ने एक पोस्ट में पं.नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी इन सबके नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़्ड लिखकर आरोप लगाया कि चारों के सत्ता में रहने के दौरान भारत में क्या-क्या गलत हुआ। नेहरूजी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वहीं सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं रहीं, यूपीए के दोनों कार्यकाल में डॉ.मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। हालांकि भाजपा ने उनके जीवित रहते कई बार उनका अपमान किया और मृत्यु के बाद अंतिम विदाई में भी अनादर ही किया। लेकिन गनीमत है कि कॉ प्रोमाइज़्ड शब्द का इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया। वैसे भी भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार और अभी खासतौर पर राहुल गांधी ही रहते हैं। तो भाजपा ने यही कहा कि राहुल गांधी का पूरा परिवार ही कॉ प्रोमाइज़्ड है। भाजपा को मुगालता है कि उसके ऐसे हमलों से अब वो सवाल उठने बंद हो जाएंगे, जिन पर नरेन्द्र मोदी बुरी तरह घिरे हुए हैं। लेकिन उसके लिए ज्यादा झटके वाली बात यह रही कि जिस समय गांधी परिवार पर वह हमला बोल रही थी, उसी समय कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने करीब एक घंटे की प्रेस कॉफ्रेंस बुधवार को की। इस में उन्होंने एपस्टीन फाइल्स पर आधारित कुछ ऐसे खुलासे किए, जिनके बाद हर देशवासी को डरना चाहिए कि आखिर देश की सत्ता किनके हाथों में है। भाजपा ने अपनी राजनीति को राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ाया, बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहीं पर राम मंदिर बनवा लिया और उसके बाद देश-विदेश के मंदिरों में नरेन्द्र मोदी को जी भर के पूजा पाठ करते हुए लोगों ने देखा है। हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ मुस्लिम अल्पसं यकों पर अत्याचारों को भी खूब बढ़ावा मिला और बड़े पैमाने पर नफरत फैलाने का काम भाजपा ने सफलतापूर्वक किया। ये कामयाबी उसे धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर मिली। लेकिन एपस्टीन फाइल्स के खुलासों ने फिर जाहिर कर दिया है कि धर्म तो भाजपा की राजनीति का केवल आवरण है, असल में विदेशी भ्रष्ट ताकतों के हाथों में देश की कमान देने का खेल भाजपा की राजनीति की असलियत है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी देश में रही, तब भी घरेलू स्तर पर धार्मिक संकीर्णता कई मौकों पर जाहिर हुई, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति परंपरागत तरीके से ही चलती रही। उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ, जिससे लगे कि हम अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन 2014 से हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि एपस्टीन फाइल्स में पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी, खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले दीपक चोपड़ा, इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और खुद जेफ्री एपस्टीन इन सबके बीच भारत की विदेश नीति और अमेरिका या इजरायल से किए जा रहे रक्षा सौदों को लेकर जो बातचीत 2014 से 2017 के बीच लगातार हुई हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या अमेरिका या अन्य देशों में हमारे दूतावास केवल दिखावे के हैं। इनसे जुड़े फैसले लेने की असली ताकत जेफ्री एपस्टीन और उसके गिरोह के पास ही है। एपस्टीन तो अब मर चुका है, लेकिन उससे हरदीप पुरी के संबंध स्थापित होने के बावजूद प्रधानमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर रहे, उस पर पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी अपने ही मंत्री के दबाव में हैं।

मोदी जी, कृपया कभी तो प्रधानमंत्री की तरह बोलिए

अनिल जैन

राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नज़रिया पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान का उनका एक भी ऐसा भाषण याद नहीं आता जो उन्होंने इस विशाल देश के प्रधानमंत्री की तरह दिया हो।

अधूरा सच, सफ़ेद झूठ, आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बयानी, तथ्यों की मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़, परनिंदा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति हिकारत का भाव, नए-नए शिगूफे, स्तरहीन मुहावरे, राजनीतिक विरोधियों पर छिछले कटाक्ष, नफ़रत भरी सांप्रदायिक तलखी, धार्मिक व सांप्रदायिक प्रतीकों का इस्तेमाल और भरपूर आत्म प्रशंसा! यही सब प्रमुख तत्व होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। मौका चाहे देश में हो या विदेश में, संसद में हो या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, चुनावी रैली हो या कोई और अवसर- हर जगह उनके भाषण में अहंकारयुक्त हाव-भाव के साथ यही सारे तत्व हावी रहते हैं। पिछले सप्ताह गुरूवार (5 फरवरी) को राज्यसभा में दिया गया भाषण भी इसका अपवाद नहीं रहा।

वैसे तो मोदी को संसद

के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देना था, लेकिन लोकसभा में 4 फरवरी को उन्होंने भाषण नहीं दिया। ऐसा उन्होंने %लोकसभा स्पीकर के कहने पर% किया। स्पीकर ओम बिड़ला ने बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक %आशंका% जताई थी कि प्रधानमंत्री अगर सदन में भाषण देने आएंगे तो कांग्रेस की कुछ महिला सांसद उन पर हमला कर सकती हैं। स्पीकर की इस आशंका से वह प्रधानमंत्री डरकर सदन में नहीं आए, जिसने तीन साल पहले 10 फरवरी, 2023 को संसद में ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बेहद फूहड़ अंदाज़ में कहा था, %देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है।

बहरहाल राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नज़रिया पेश करते हैं। इसी क्रम में वे बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों और आलोचनाओं का भी जवाब देते हैं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं किया। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने इस गंभीर मौके पर भी एक मोहल्ला स्तर के नेता की तरह चुनावी भाषण दिया। कुछ साल पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक

टीवी इंटरव्यू में कहा था कि %देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मिली है। %कंगना की इस बात पर खुश होकर मोदी ने उन्हें सांसद बनवा दिया और गुरूवार को राज्यसभा में कंगना द्वारा कही बात की तज़ाब ही यह जताने की कोशिश की कि देश ने जो कुछ तरक्की की है, वह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद की ही है।

उन्होंने कहा कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें किसी के पास देश को लेकर न तो कोई सोच थी, न कोई दृष्टि और न ही इच्छाशक्ति। उन्होंने देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। उन्होंने कहा, मैं देशवासियों का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी (पूर्व प्रधानमंत्रियों की) गलतियों को ठीक करने में लग रही है।

उनके समय जो देश की छवि बनी थी, उसे धोने में मेरी ताकत लग रही है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की आलोचना व निंदा करने का तो मोदी पर मानो जुनून सवार रहता है और इस सिलसिले में जो मुंह में आता है वह बोल जाते हैं। ऐसा करने में वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनकी अशोभनीय गलतबयानी से देश-दुनिया में उनकी खिल्ली उड़गी और लोग उनकी पढ़ाई-लिखाई व उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएंगे। राज्यसभा में दिए अपने भाषण में भी मोदी ऐसा करना नहीं भूले। इस सिलसिले में उन्होंने इंदिरा गांधी के ईरान में दिए गए एक भाषण के हवाले से कहा कि, जवाहरलाल नेहरू

के समय देश की जनसं या 35 करोड़ थी और नेहरू कहते थे कि मेरे सामने 35 करोड़ समस्याएँ हैं।

इसी तरह इंदिरा गांधी के समय देश की जनसं या 57 करोड़ थी और इंदिरा जी ने कहा था कि, मेरे सामने 57 करोड़ समस्याएँ हैं। मोदी का यह बताना या तो उनकी क्षुद्रता का परिचायक है या फिर उनकी नासमझी का। यह उनके भाषण के नोट्स बनाने वाले नौकरशाहों की शरारत भी हो सकती है कि उन्होंने मोदी को गलत नोट्स बनाकर थमा दिए हों जिन्हें मोदी ने संसद में पढ़ दिए।

दरअसल नेहरू से जब किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि %आपके सामने कितनी समस्याएँ हैं, तो नेहरू ने कहा था कि देश के 35 करोड़ लोगों की समस्याएँ मेरी समस्या हैं; और इसी तरह इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश के 57 करोड़ लोगों की समस्याओं को मैं अपनी समस्या मानती हूँ। प्रधानमंत्री अपने भाषण का स्तर गिराने में यहीं नहीं ठहरे। इससे भी नीचे उतरते हुए उन्होंने कहा कि चोरी करना नेहरू-गांधी परिवार का पुस्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया।

वैसे अब्बल तो कोई क्या सरनेम लगाता है, यह बहस का विषय नहीं हो सकता और संसद में तो कतई नहीं, फिर भी अगर मोदी को इसका शौक है तो उन्हें इस बारे में बोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि गांधी सरनेम किसी जाति या संप्रदाय विशेष में नहीं होता है बल्कि यह इत्र-फुलेल से जुड़े व्यवसाय से ताद्दुक्त रखाता है। यह सरनेम सिर्फ वैश्य वर्ग

में ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, पारसी आदि समुदायों में भी होता है। मोदी ने यह सिलसिला सिर्फ चुनावी सभाओं तक ही सीमित नहीं रखा है।

संसद में, संसद के बाहर विभिन्न मंचों पर और यहां तक कि विदेशों में भी वे विपक्षी नेताओं पर निजी हमले और अपमानजनक बातें करने से नहीं चूकते हैं। फिर, विपक्ष शासित राज्यों के प्रति उनकी सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भी केंद्र और राज्यों के बीच खटास पैदा कर दी है। दरअसल विरोधी दलों और उनके नेताओं के प्रति मोदी की अपमानजनक बातें शुरू में जरूर अटपटी लगती थीं।

चूँकि भाजपा और मोदी ने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, इसलिए विपक्षी नेताओं ने उनकी ऐसी बातों को यह सोचकर बर्दाश्त किया कि जीत का खुमारी उतर जाने पर प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श में सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और भाषायी शालीनता का पालन करने लगेगे। जब ऐसा नहीं हुआ और लगने लगा कि यही मोदी की स्वाभाविक राजनीतिक शैली है और वे बदलने वाले नहीं हैं, तब विपक्षी नेताओं के सन्न का बांध टूटा और उसमें सारी राजनीतिक शालीनता और मर्यादा बहती चली गई।

ज्यादा जागे बॉलीवुड मूवी टिकट कविता संग्रह साक्षात्कार तकनीक गाइड देश में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी मु यमंत्री या नेता होगा जिसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बातें या गाली-गलौज नहीं की होगी। मोदी उन्हें भ्रष्ट, परिवारवादी, लुटेरा, नक्सली, आतंकवादियों का

समर्थक और देशद्रोही तक करार देने में कोई संकोच नहीं करते। इस सिलसिले में वे विपक्ष की महिला नेताओं को भी नहीं ब. शते। वे उनके लिए बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। विपक्षी नेताओं के प्रति मोदी के अपमानजनक बर्ताव का ही नतीजा है कि आज केन्द्र-राज्य संबंध किसी भी समय के मुकाबले सबसे बदतर स्थिति में हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब मोदी किसी विपक्ष शासित राज्य के दौरे पर गए तब वहां के मु यमंत्री उनकी आगवानी करने नहीं पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्षी दलों को अपने, अपनी पार्टी और देश के दुश्मन के तौर पर प्रचारित करते हुए उन्हें खत्म करने का खुला ऐलान किया है।

वे हर जगह डबल इंजन की सरकार का ऐसा प्रचार करते हैं, जैसे विपक्ष की सारी सरकारें जनविरोधी, देश-विरोधी और विकास-विरोधी हैं। मोदी की इस राजनीति ने विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए आज अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर आंच आ रही है और उनकी बेअदबी हो रही है तो इसके लिए प्रधानमंत्री का अंदाज़-ए-हुकूमत और अंदाज-ए-सियासत ही जि मेदार है। कितना अच्छा होता कि मोदी भाषा और संवाद के मामले में भी उतने ही नफासत पसंद या सुरुचिपूर्ण होते, जितने वे पहनने-ओढ़ने और सजने-संवरने के मामले में हैं। एक देश अपने प्रधानमंत्री से इतनी सामान्य और जायज अपेक्षा तो रख ही सकता है। उनका बाकी अंदाज-ए-हुकूमत चाहे जैसा भी हो।

भारत पर नजर रखो, क्या दिन ला दिए मोदी जी!

शकील अख्तर

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह तो बता रहे हैं कि कौन कौन से उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। मगर यह नहीं बता रहे कि कौन कौन से आएंगे। सारा खेल इसी में छुपा है। अमेरिका जो चाहेगा वह आएगा। जीएम (जेनेटिक मोटिफाइड) फसलों के लिए वह भारत को प्रयोगशाला बनाएगा। यही कहा जा रहा है कि मीडिल क्लास चेत जाए। यह जीएम फसलें इस पीढ़ी को नहीं अगली कई पीढ़ियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगी यह सोचना भी बहुत डरावना है। डीएनए बदल जाएगा।

किसी से लड़ना, अवाइड करना या और कुछ भी तिरस्कार वगैरह इन सबसे बुरी बात समझी जाती है नजर रखना। नजर किस पर रखी जाती है? वह तो सब ठीक है अपराधी वगैरह। लेकिन उससे भी बुरी बात है नजर अपने आश्रित पर रखी जाती है। शब्द बहुत गंदा है मगर सच वही है कि गुलाम पर। कि वह गुलामी से बाहर जाने की तो नहीं सोच रहा। नजर रखो इस पर। ज्यादा जागे भाषा सीखने का कोर्स ऑनलाइन समाचार पोर्टल साक्षात्कार तो मोदी जी आज भारत को इस स्थिति पर ले आए कि अमेरिका के अधिकारी हम पर निगाह रखेंगे। अब क्या करें? हद तो यह हो गई कि इस शर्मनाक स्थिति में लाने को मोदी अपनी शान समझ रहे हैं! संसद परिसर में एनडीए के सांसदों से अपना स्वागत

करवा रहे हैं। हार पहन रहे हैं। जीत का!

हम किस से तेल खरीदेंगे किस से नहीं यह अमेरिका तय करेगा। और हम उसके अनुसार करेंगे। मगर फिर भी वह हम पर निगाह रखेगा। इससे ज्यादा शर्म की, अपमान की बात और क्या हो सकती है। लेकिन क्या यह भारत का अपमान है? ऊपर से देखने में हैं। मगर वास्तव में यह मोदी का पराभव है। सारी नकली कलाई खुल गई। 56 इंच की छाती, लाल आंखों और एक अकेला सब पर भारी की असलियत सब के सामने आ गई। अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी के शब्दों में नरेन्द्र ...सरेन्द्र-।, दृष्टाश् ऋदुश् - उलटा पड़ सकता है किताब को लेकर मुकदमे का दांव बाहर इस तरह सरेन्द्र किया और यहां राहुल का सामना होने से डर कर लोकसभा में नहीं आए। राहुल ने सुबह कहा था मोदी जी मैं लोकसभा में आने की हि मत नहीं है। उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था। मगर वे वास्तव में नहीं आए और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष से कहलवाया यह गया कि मोदी को सदन में खतरा था। विपक्ष की महिला सांसदों से। इसलिए नहीं आए।

प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा! वह भी महिला सांसदों से! बहुत बड़ा मजाक हो गया यह। और यहीं से मोदी जी की उलटी गिनती की शुरुआत हो जाती है। विदेशों

से भारत की निगरानी का फरमान आता है और उन्हें जवाब देना तो दूर वे देश में अपनी लोकसभा में जिसके वे नेता हैं वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें वहां खतरा दिखता है। दृष्टाश् ऋदुश् - एक हाथ से ताली नहीं बजती अमेरिका से डील मोदी की है। कमजोर और लाचार भारत दिख रहा है। भारत न कभी था न कभी है। लेकिन जैसा कि भक्तों ने मोदी का मतलब भारत कर दिया था। वैसे ही अब मोदी के कमजोर होने से अमेरिका भारत को कमजोर समझ रहा है। उस पर नजर रखने की बात कर रहा है। इसका जवाब विपक्ष तो कड़े शब्दों में दे ही रहा है।

कांग्रेस ने साफ कह दिया कि आपकी जो भी सीक्रेट अमेरिका के पास हों हमें कोई मतलब नहीं है। आप इस वजह से सरेन्द्र कर दीजिए मगर भारत नहीं झुकेगा। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चैयरमेन पवन खेड़ा ने यह कहते हुए एपस्टीन फाइल का भी जिक्र किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर चुके हैं। एपस्टीन फाइल में नाम आया है। संदेश यही जा रहा है कि एपस्टीन फाइल की वजह से ट्रंप मनमानी कर रहा है।

पहले उसने सीज फायर करवाया। और फिर यह डील। जो पूरी तरह इकतरफा है। भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ। भारत का जो सामान पहले अमेरिका 3 परसेन्ट टैरिफ देकर जाता था। अब 18 परसेन्ट देकर

जाएगा। सामान्य शब्दों में पहले भारत के बने सामान पर अमेरिका केवल तीन प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लेता था। फिर उसने हमें धमकाते हुए पहले 50 प्रतिशत किया। सौ प्रतिशत की धमकी दी। फिर 25 प्रतिशत पर लाया। और अब जो नई डील हो गई है उस में 18 प्रतिशत लेगा। मतलब तीन से 18 प्रतिशत बढ़ाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री इस अपनी जीत बताते हुए विजय माला पहन रहे हैं।

ज्यादा जागे क्षेत्रीय व्यंजन रेसिपी चुनावी कवरेज राजनीतिक विश्लेषण और देखिए। डील में इससे भी ज्यादा जो खतरनाक पहलू है जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है वह है अमेरिका के लिए अपना पूरा बाजार खोल देना। अमेरिका कह रहा है कि इस डील से उसका किसान मालामाल हो जाएगा। और हमारे किसान का दिवाला निकल जाएगा। अमेरिका से जो कृषि और डेयरी उत्पाद आएंगे वह टैरिफ फ्री होंगे। मतलब उस पर भारत एक पैसा भी शुल्क (टैरिफ) नहीं लगाएगा। अमेरिका को जो भी अतिरिक्त उत्पादन है वह सब यहां डंप किया जाएगा। भारत का किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि यह तीन काले कानूनों से बड़ी तबाही होने जा रही है। उसके साफ शब्द हैं कि उन्हें सरकार की सफाईयों पर भरोसा नहीं है। डील में जितना बताया जा रहा

है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। अमेरिका का साफ कहना है वह इसके जरिए 500 अरब डालर का माल भारत में बेचेगा। 500 अरब डालर मतलब 45 लाख करोड़ रुपए! यह भी समझना मुश्किल है इतना रुपया कितना होता है? तो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि अभी जितना माल विदेशों से भारत आता है उसका ढाई गुने से ज्यादा केवल अमेरिका से हमें आयात करना होगा। और माल आता हो तो किसका पैसा जाता है। आम भारतीय का ही।

उससे यही माल खरीदवाया जाएगा। किसकी कीमत पर? भारतीय किसान और पशुपालक की कीमत पर। प्रचार और कीमतों में का पीटिशन करवा कर वे भारतीय किसान को मुकाबले से बाहर कर देंगे। खतरे बहुत बड़े हैं। जनता को ही समझना होंगे। और अगर नहीं समझती तो वह आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी की कहानी लिखने में खुद भी शामिल मानी जाएगी। कांग्रेस ने मध्यम वर्ग को सचेत किया है।

माहौल वही बनाता है। मोदी मोदी का जाप सबसे पहले उसी ने किया था। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह तो बता रहे हैं कि कौन कौन से उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। मगर यह नहीं बता रहे कि कौन कौन से आएंगे। सारा खेल इसी में छुपा है। अमेरिका जो चाहेगा वह आएगा। जीएम (जेनेटिक मोटिफाइड) फसलों के लिए

वह भारत को प्रयोगशाला बनाएगा। यही कहा जा रहा है कि मीडिल क्लास चेत जाए। यह जीएम फसलें इस पीढ़ी को नहीं अगली कई पीढ़ियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगी यह सोचना भी बहुत डरावना है। डीएनए बदल जाएगा। यह संयोग प्रयोग डीएनए ऐसे शब्दों का प्रधानमंत्री बहुत उपयोग करते हैं। मगर क्या इनका मतलब उन्हें मालूम है? भारत में जीएम फसलों पर रोक है। केवल कपास की खेती की अनुमति है। यह बहुत बड़ी बहस है कि खाने-पीने की चीजें जीएम होना चाहिए या नहीं और इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग भारतीय लोगों पर किया जाएगा? बहुत संक्षेप में जीएम मतलब किसी बीज, जीव या पौधे के जीन को दूसरे में आरोपित कर एक नई प्रजाति विकसित करना। जीएम फसलों की जरूरत वहां होती है जहां उत्पादन कम हो। मगर भारत में तो इन्दिरा गांधी ने हरित क्रांति करके देश में अतिरिक्त अनाज पैदा करवा दिया था। किसान और कृषि वैज्ञानिकों ने उनका साथ दिया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अमेरिका की खाद्य और कृषि उत्पाद व्यापार में मौजूद सुरामी बाधाओं को पार करने पर सहमति जताई है। इससे साफ और क्या होगा? सरकार कितना ही छुपाने की कोशिश करे इसका मतलब साफ है जीएम फसलों के लिए दरवाजे खोलना।



विविध समाचार



बजट कंसल्टेशन बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अहम सुझाव, बजट आंकड़ों का नहीं जन आकांक्षाओं का दस्तावेज होगा : नायब सैनी

चंडीगढ़ 05/03 (संवाददाता): हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करना एक सशक्त और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके।



पंचकूला में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि उन्होंने राज्य के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने का सुझाव दिया है।

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने की भी सिफारिश की गई है, ताकि

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बैठक में सांसदों एवं विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव रखे, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल योजना के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, स्टैडियमों के साथ-साथ निजी स्कूल, कॉलेज और

गौशालाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आएगी और हरियाणा हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेगा। अनिल विज ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे आधुनिक ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने

कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर वाहन चार्जिंग के साथ-साथ यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट, स्वच्छ शौचालय और आराम की सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे परिवारों को यात्रा के दौरान सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशभर में लोगों से संवाद कर बजट से जुड़े सुझाव ले रहे हैं और इसी कड़ी में सभी सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। विपक्ष के सांसदों और विधायकों को भी बैठक में आमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई भी विपक्षी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इस पर टिप्पणी करते हुए अनिल विज ने कहा कि संभवतः विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पूर्व में विपक्ष ऐसी बैठकों में भाग लेता रहा है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को सम्मान न मिलने के सवाल पर

प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रही है और उसका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है। राहुल गांधी के हालिया कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अनिल विज ने कहा कि अंग्रेज और मुगल इसलिए गए क्योंकि वे विदेशी थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की मिट्टी से जुड़ी पार्टी है। भाजपा इसी धरती पर जन्मी है और देश की संस्कृति, राष्ट्रभाव और विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में विदेशी अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा अंग्रेजों के साथ तालमेल के लिए की गई थी। यदि विदेशी दलों के जाने की बात होती है तो कांग्रेस जाएगी, भाजपा नहीं, क्योंकि भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है।



चंडीगढ़ 05/03 (संवाददाता): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों पर गंभीरता से विचार कर ऐसा बजट तैयार किया जाएगा जिससे प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद की मुस्कान आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 2026-27 का राज्य बजट आंकड़ों का नहीं बल्कि जन आकांक्षाओं का दस्तावेज होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में हरियाणा विजन 2047 कार्यक्रम पर मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों विधायकों तथा मंत्रियों ने बजट को लेकर अपने सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 जनवरी से शुरू की गई एआई आधारित ऐप के माध्यम से अब तक 9 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। नागरिक 31 जनवरी तक पोर्टल के जरिए अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। उपयोगी और व्यावहारिक सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने में आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण

भूमिका रहेगी। उन्होंने बताया कि बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया 6 जनवरी को गुरुग्राम से शुरू हुई थी जिसका अंतिम चरण अब पूरा हो गया है। अब तक 12 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1597 हितधारकों से संवाद हुआ और 1513 सुझाव प्राप्त हुए। ये बैठकें उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य महिला वर्ग किसान सरपंच पार्षद युवा और विभिन्न संगठनों के साथ की गईं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सरकार का नहीं बल्कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता का होगा और यह वर्तमान जरूरतों तथा भविष्य की योजनाओं के बीच मजबूत सेतु बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक हजार एकड़ भूमि पर स्मार्ट जोन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन के जरिए प्रदेश के विकास को नई दिशा दे रही है।

शिमला और मनाली में खराब मौसम के कारण पर्यटकों को भारी असुविधा

मनाली 05/03 (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों मनाली और शिमला में भारी बर्फबारी के कारण हजारों पर्यटक घंटों तक फंसे रहे। सड़क संपर्क टूटने और यातायात प्रबंधन के विफल होने से इन पर्यटकों को भोजन, गर्म कपड़ों और आश्रय के बिना भारी कठिनाइयों का सामना करना

पड़ा। मनाली में लगभग दो फीट ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे 23 जनवरी से नेशनल हाईवे 60 घंटों से अधिक समय तक अवरुद्ध रहा। इस स्थिति ने प्रशासन, सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बर्फ हटाने का काम अधूरा रहने और वाहनों के फिसलने के कारण मनाली से कोठी

तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई पर्यटकों ने अपने वाहन छोड़ दिए और पैदल ही होटलों तक पहुंचे, जबकि कई लोगों को पूरी रात कारों के भीतर ही बितानी पड़ी। कुल्लू और मनाली के बीच गोजरा पर 'लेफ्ट बैंक रोड' पर भी भारी जाम देखा गया। यहां स्थानीय निवासियों ने आगे आकर फंसे हुए लोगों को भोजन और शरण

दी। एसडीएम रमन कुमार शर्मा ने बताया है कि प्रशासन लगातार काम कर रहा है और यातायात धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया कि बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात की गई है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी को और अधिक बारिश व बर्फबारी का अनुमान जताया है, जिसके बाद प्रशासन ने

पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक सलाह का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा के सौरभ जोशी होंगे चंडीगढ़ के नए मेयर

चंडीगढ़ 05/03 (संवाददाता): चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं। भाजपा को 18 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को 7 और आप उम्मीदवार को 11 वोट मिले हैं। वोटिंग से पहले ही भाजपा की जीत के कयास लगाए जा रहे थे। इस बार चुनाव सिफ्रेट बलैट वोटिंग की जगह पार्षदों के

हाथ खड़े कर हुआ। पहली बार तीनों पार्टियां मेयर का चुनाव लड़ रही थीं। पिछले 2 चुनाव में AAP और कांग्रेस का गठबंधन था। मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग होगी। मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद सौरभ जोशी भावुक हो गए और भाषण देते हुए बोले कि मेरे पिता ने कहा था कि तुम सही रास्ते पर चलो, सब बेहतर होता जाएगा।

प्रकृति पूजा, शिव व देवी की पूजा आदि कई समानताएं हैं सरना व सनातन में

जनवरी में द्विदिवसीय रांची, झारखण्ड यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघप्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जनजाति संवादकार्यक्रम में सरना पूजा-पद्धति की सनातन धर्म से समानता को लेकर की गई टिप्पणी के बाद यह मुद्दा बहस के केंद्र में है। कार्यक्रम के दूसरे दिन 24 जनवरी को जनजाति संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवतने स्पष्ट रूप से कहा कि सरना एक पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म। हिन्दू धर्म की परिभाषा देते हुए भागवत ने तर्क दिया कि हिन्दू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी जीवन पद्धति और साथ रहने का तरीका है। उन्होंने आदिवासियों को सनातन संस्कृति और धर्म का मूल आधार बताया। उनके अनुसार, जिस दिन जनजाति समाप्त होगी, उसी दिन सनातन भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि सरना को अलग धर्म के रूप में देखना समाज को तोड़ने का प्रयास है और बाहरी ताकतों को शोषण का मौका देना है। भले ही कोई पेड़ की पूजा करे या पहाड़ की, सभी का भाव एक ही है, जो सनातन मूल्यों से जुड़ा है। उनके इन बयानों पर प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे झारखण्ड में बयानों की बाढ़ आ गई, अनेक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, जहां विपक्ष ने सरना धर्म कोडकी मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके रुख की आलोचना की, वहीं अनेक जनजातीय नेताओं ने उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक हम जनजातीय बन्धु भी अपने आंगन में चीरा झंडा नहीं बल्कि महावीरी झंडा फहराया करते थे, आंगन में तुलसी चबूतरा में लगे तुलसी माता की पूजा

किया करते थे और हिन्दू पर्व-त्योहारों में खुशी से भाग लेते थे और तत्संबंधी पूजा पाठ विधि-विधानपूर्वक करते थे। आज भी अधिकांश सरना आदिवासी रामनवमी, नवरात्र, महाशिवरात्रि, होली आदि पर्व त्योहारों का आयोजन करते हैं और पूजा-पाठ में भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि सरना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थात् धार्मिक पहचान के रूप में उदय 1930 के दशक में हुआ था, जब सरना धर्म अर्थात् सरनावाद को एक सामूहिक धार्मिक पहचान के रूप में छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखण्ड में प्रचारित किया गया था। सरना शब्द मूल रूप से मुंडारी भाषा के शब्द सरसे निकला है, जिसका अर्थ पवित्र साल वृक्षों का झुरमुट होता है। परंपरागत रूप से यह शब्द आदिवासियों के पूजा स्थल (सरना स्थल) को संदर्भित करता है। हालांकि यह मूल रूप से मुंडारी शब्द है, लेकिन कालांतर में उरांव, हो आदि अन्य जनजातियों ने भी इसे अपनी धार्मिक पहचान के रूप में अपनाया, जो आदिवासियों में इसकी सामूहिक स्वीकार्यता का द्योतक है। सरकारी दस्तावेजों में 1970 के दशक से आदिवासियों ने जनगणना के दौरान अपनी धार्मिक पहचान सरनाके रूप में दर्ज करानी शुरू की। 1971 की जनगणना में पहली बार लगभग 3,00,000 लोगों ने स्वयं को सरना धर्मावलंबी बताया था। सरना कोड की पहली औपचारिक मांग 1980 के दशक में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखण्ड प्रदेश के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद कार्तिक उरांव द्वारा की गई थी। वस्तुतः एक विशिष्ट पूजा स्थल के रूप में यह शब्द प्राचीन काल से प्रचलित है, लेकिन एक संगठित धार्मिक शब्द के रूप में इसका व्यापक प्रयोग 1930 के दशक से शुरू

हुआ। 1980 के दशक में इसकी मांग शुरू है, और अब यह मांग एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। सरना और सनातन हिन्दू धर्म के बीच संबंध को लेकर कई मत और दृष्टिकोण प्रचलित हैं। अनेक आदिवासी संगठनों और विद्वानों का तर्क है कि सरना एक पूरी तरह से स्वतंत्र प्रकृतिआधारित धर्म है। इनके अनुसार सरना धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं होती, बल्कि पेड़ों, पहाड़ों और नदियों (प्रकृति) की सीधे पूजा की जाती है। इसका कोई धर्मग्रंथ नहीं है। सनातन धर्म के वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों के विपरीत सरना की परंपराएं मौखिक हैं और इनमें कोई लिखित धर्मग्रंथ नहीं होता। सरना समाज में हिन्दू धर्म जैसी जाति अथवा वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। सरना मान्यताओं में आमतौर पर पुनर्जन्म या कर्मके सिद्धांत की वह अवधारणा नहीं है जो सनातन धर्म का मूल आधार है। अनेक आदिवासी लोग अंतिम संस्कार में मृतक का शव दाह करते हैं, लेकिन कई आदिवासी समुदायों में शवों को जलाने के बजाय दफनाने की परंपरा है। सरना को सनातन का हिस्सा मानने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कई धार्मिक व सांस्कृतिक संगठनोंका मानना है कि सरना वास्तव में सनातन धर्म का ही एक वनवासी रूप है। प्राचीन ऋषि-मुनियों के अरण्य संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। सनातन धर्म में भी तुलसी, पीपल, पर्वत, नदियां आदि प्रकृति की पूजा का विधान है, इसलिए यह भिन्न नहीं है। दोनों के ही साझा सांस्कृतिक मूल्य हैं। दोनों ही जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं और कई स्थानीय देवता व परंपराएं आपस में मिलती-जुलती हैं। दोनों का ऐतिहासिक जुड़ाव भी समान है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि

आदिवासी प्राचीन काल से ही हिन्दू समाज का अभिन्न अंग रहे हैं, जिसका प्रमाण रामायण-महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में भी अंकित मिलते हैं। वर्तमान में झारखण्ड जैसे राज्यों में सरना धर्म कोडकी मांग जोर पकड़ रही है ताकि आगामी जनगणना में आदिवासियों को अपनी एक अलग धार्मिक पहचान दर्ज करने का विकल्प मिल सके। आधिकारिक तौर पर अभी इसे एक अलग धर्म की मान्यता नहीं मिली है और जनगणना के दौरान यह हिन्दू अथवा अथवा अन्यश्रेणी में दर्ज किया जाता रहा है। सरना और सनातन दोनों ही प्राचीन और सांस्कृतिक गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों धर्मों में एकता और समरसता का भाव है, और दोनों ही धर्मों में प्रकृति और जीवन की महत्ता को माना जाता है। सरना धर्म में भी एक सर्वशक्तिमान शक्ति को माना जाता है, जिसे थान कहा जाता है, जबकि सनातन धर्म में भगवान (भूमि, गगन, वायु, आकाश अर्थात् अंतरिक्ष अग्नि व नीर) को माना जाता है। महादेव, पार्वती, श्रीराम, बजरंग बली हनुमान आदि अनेक सनातन देवी-देवता पूज्य माने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों धर्मों के बीच एकता और समानता को देखते हुए इन दोनों धर्मों को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक नई दिशा दी जा सकती है। सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का बहुत महत्व है। वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथोंमें भी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि आदि प्रकृति के विभिन्न तत्वों की महत्ता, उपयोगिता के महानजर उनके प्रति पूज्य भाव दिखलाया गया है। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्रकृति को देवतुल्य अर्थात् भगवान का रूप माना है और उसकी पूजा करने का महत्व बताया है।



ऑपरेशन साइबर कवच, ओडिशा में २१ हजार से ज्यादा म्यूल अकाउंट, २७३ लोग गिरफ्तार

भुवनेश्वर ०५/०३ (संवाददाता): ऑपरेशन साइबर कवच शुरू होने के बाद से, पूरे राज्य में पुलिस ने 21,162 खचर बैंक अकाउंट वेरिफाई किए हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव के नतीजे में खचर बैंकिंग एजिटिविटीज से जुड़े 696 साइबर केस, ATM से कैश निकालने से जुड़े 31 केस, चेक निकालने से जुड़े 25 केस, और नकली SIM कार्ड और PoS के गलत इस्तेमाल से जुड़े 15 केस रजिस्टर हुए हैं। अब तक 273 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नए पकड़े गए मामलों से जुड़े 4,860 संदिग्ध अकाउंट होल्डर्स और मदद करने वालों के साथ-साथ पहले से दर्ज 145 FIR को भी लीगल नोटिस जारी किए गए इस कैंपेन में जिलों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। कटक जिले में, पुलिस ने 50 बेनामी अकाउंट वेरिफाई किए और ज्यूल बैंकिंग और नकली SIM/PoS एजिटिविटी से जुड़े केस रजिस्टर किए, नए और पुराने दोनों मामलों में नोटिस जारी



किए। जगतसिंहपुर और जाजपुर जिलों ने भी अकाउंट वेरिफाई और केस रजिस्टर होने की सूचना दी, जिसमें जाजपुर ने चल रही जांच से जुड़े कई लोगों को नोटिस जारी किए। पुरी जिला पुलिस ने 189 बेनामी अकाउंट वेरिफाई किए और छह केस रजिस्टर किए, जबकि बरगढ़ जिला पुलिस ने न केवल अकाउंट वेरिफाई किए और केस रजिस्टर किए, बल्कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पश्चिमी ओडिशा में, बलांगीर, झारसुगुड़ा और संबलपुर जिलों ने वेरिफिकेशन

ड्राइव चलाई और नए केस रजिस्टर किए, जिसमें संबलपुर में गिरफ्तारियां हुईं। सुबर्नपुर ने एक केस रजिस्टर किया और नोटिस जारी किए, जबकि ज्योंझर और राउरकेला में कई केस और गिरफ्तारियां दर्ज की गईं। सुंदरगढ़, बालासोर और कटक ने भी वेरिफिकेशन किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की। गंजम जिले की पुलिस ने एक केस दर्ज किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अंगुल जिले ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें झरू और चेक से जैसे निकालने के

मामलों के साथ-साथ कई ज्यूल बैंक केस दर्ज किए गए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों लोगों को नोटिस जारी किए गए। मलकानगिरी, केंद्रपाड़ा और खोरधा जिलों ने वेरिफिकेशन और कार्रवाई जारी रखी, जिसमें खोरधा ने झरू से पैसे निकालने से जुड़े मामले दर्ज किए। नयागढ़ में, पुलिस ने 200 से ज्यादा बेनामी अकाउंट वेरिफाई किए और बड़ी संख्या में संदिग्धों को नोटिस जारी किए। भद्रक और मयूरभंज ने बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन

किया, जबकि भुवनेश्वर ने 378 बेनामी अकाउंट वेरिफाई किए और पहले की सड़क से जुड़े नोटिस जारी किए। बरहामपुर पुलिस ने एक पुराने केस से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया, और बौध जिले ने सभी वेरिफाई किए गए अकाउंट होल्डर्स को नोटिस जारी किए। कंधमाल, देवगढ़, ढेंकनाल, कालाहांडी, कोरापुट, नबरंगपुर और नुआपाड़ा जिलों में भी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए गए और कैंपेन के तहत नोटिस जारी किए गए। डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए फोर्स के कमिटमेंट को दोहराते हुए, DGP खुरानिया ने कहा कि आने वाले दिनों में इस ड्राइव को और तेज किया जाएगा। जिला लेवल पर मिलकर कार्रवाई करने और साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फाइनेंशियल तरीकों को खत्म करने पर ध्यान देने के साथ, ऑपरेशन साइबर कवच साइबर क्राइम-री ओडिशा बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

राउरकेला इस्पात सयंत्र में आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिह्नित करने के लिए प्रतियोगिताएं हुईं शुरू



राउरकेला ०५/०३ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात सयंत्र ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक हिस्से के रूप में, आकर्षक प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला का आयोजन शुरू कर दिया है जो कर्मचारियों से भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिताओं की श्रृंखलामहिला सशक्तिकरण

विषय पर आरएसपी-स्तरीय स्पोर्ट प्रतियोगिता के साथ शुरू हुई। प्रतियोगिता आरएसपी के सभी कर्मचारियों के लिए खुली थी, जिसमें सात सदस्य शामिल थे। इस कार्यक्रम में समाज और कार्यस्थल में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने वाले शक्तिशाली प्रदर्शनों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन- ज्ञानार्जन एवं विकास), श्री पी. के. साहू और

महाप्रबंधक (जनसंपर्क) और संचार मुख्य, श्रीमती अर्चना शतपथी प्रतियोगिता के निर्णायक थे। वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन- ज्ञानार्जन एवं विकास), सुश्री अर्चनापूर्ण बेहेरा ने कार्यक्रम का समन्वय किया। विजेता टीम 6 मार्च को सिविक सेंटर में होने वाली सेल-स्तरीय स्पोर्ट प्रतियोगिता में आरएसपी का प्रतिनिधित्व करेगी।

सरकार ने लैंड रेवेन्यू और वॉटर सेस की वसूली का आदेश दिया

भुवनेश्वर ०५/०३ (संवाददाता): ओडिशा सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के खत्म होने के करीब आने पर पेंडिंग लैंड रेवेन्यू और वॉटर सेस वसूलने के लिए एक सख्त मुहिम शुरू की है। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डॉ. अरविंद कुमार पाधी ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को कलेक्शन में तेजी लाने और बिना देर किए रेवेन्यू टारगेट पूरे करने का निर्देश दिया। डॉ. पाधी ने लैंड रेवेन्यू (भूराज्यस्व) और इरिगेशन वॉटर सेस (जलकारा) से बकाया वसूलने की जल्दी पर जोर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लैंड रेवेन्यू से 980 करोड़ और वॉटर सेस से 25.32 करोड़ के बड़े लक्ष्य तय किए, जो राज्य के नॉन-टैक्स रेवेन्यू सोर्स का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने रेवेन्यू



डिविजनल कमिश्नरों को हर हज्ते रिप्यू करने का निर्देश दिया, ताकि प्रोग्रेस की कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग हो सके। कलेक्टरों को सतर्क रहना चाहिए, रेगुलर रिपोर्ट देनी चाहिए और तय आंकड़े हासिल करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए। यह निर्देश ओडिशा के अपने इंटरनल रेवेन्यू सोर्स को मजबूत करने पर फोकस को दिखाता है ताकि कमी को कम किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर जल्द ही

खत्म होने वाला है, इसलिए सरकार का मकसद है कि बकाया समय पर मिले और फाइनेंशियल डिस्ब्लिफ को मजबूत किया जाए। सभी जिलों के अधिकारियों को रिकवरी ड्राइव तेज करने, प्रोसेस को आसान बनाने और अकाउंटवेबिलिटी पक्का करने का काम सौंपा गया है। यह कदम बजट टारगेट को पूरा करने और राज्य की फाइनेंशियल मजबूती को मजबूत करने के प्रशासन के पक्के इरादे को दिखाता है।

पारादीप रेप और मर्डर केस में दो लोग गिरफ्तार

पारादीप ०५/०३ (संवाददाता): ओडिशा पुलिस ने पारादीप में एक महिला के कथित रेप और मर्डर के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जगतसिंहपुर के पुलिस सुपरिटेण्डेंट अंकित वर्मा ने कहा कि यह घटना रात को हुई। उन्होंने बताया रात को एक महिला एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरकर मर गई। 23 की सुबह शिकायत मिली और उसके बाद छह केस दर्ज किया गया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कई बातें सामने आईं। तितौल थाने में, मृतक के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी। यह पता चला कि यह कोई अचानक हुआ मामला नहीं था। आरोपी, शुभम कुमार, जो बिहार के धनबाद, मधुबन थाने का रहने वाला है, इसमें शामिल था। उसने उसके साथ रेप किया और फिर

उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया... आगे की जांच में उसके बायफेंड, सोमनाथ ओझा के बारे में जानकारी मिली। 22 की रात को, वह सोमनाथ से मिलने गई थी, जहाँ किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। बाद में, सोमनाथ ने उसे मार्केट एरिया के पास छोड़ दिया, जहाँ उसकी मुलाकात शुभम से हुई, जो पारादीप जा रहा था। क्योंकि वह उसी तरफ जा रही थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले गया। फिर शुभम उसे अपने घर ले गया, जहाँ उसने उसके साथ रेप किया और उसे बिल्डिंग की चौथी मंजिल से फेंक दिया... इस दौरान वर्मा ने कहा, जांच के दौरान शुभम के मोबाइल फोन से एडल्ट वीडियो कंटेंट भी मिला। पुलिस को जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से एडल्ट वीडियो कंटेंट भी मिला।

नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

सुंदरगढ़ ०५/०३ (संवाददाता): एक अहम फैसले में, सुंदरगढ़ की स्पेशल POCSE कोर्ट ने 2016 में एक नाबालिग लड़की के रेप के लिए एक आदमी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया, और जुर्माना न देने पर एक साल की और साधारण जेल की सजा दी। दोषी की पहचान अरुण कालेत (30) के तौर पर हुई है, जो लेफ़ोपाड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके का रहने वाला है, जहाँ यह क्राइम हुआ था। प्रॉसिज्यूशन के मुताबिक, यह घटना 10 जनवरी, 2016 की शाम को हुई थी। उस समय करीब 9 साल की नाबालिग पीड़िता शाम करीब 5:30 बजे शौच के लिए अपने घर के पीछे गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई, तो उसके परिवार ने उसे ढूँढना शुरू किया, लेकिन वह नहीं मिली। अगली सुबह, परिवार वालों ने उसे सुरगुड़ा रोड पर अकेली और बेबस पाया। जब उसे बचाया गया और पूछताछ की गई, तो



सदमे में आई लड़की ने बताया कि उसके साथ सेज्शुअल असॉल्ट हुआ था। उसने बताया कि आरोपी अरुण कालेत ने उसका मुँह बंद कर दिया, उसे जबरदस्ती उठाया और डेमुल गांव के पास एक जगह ले गया, जहाँ उसने जुर्म किया। फिर वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। डर और शर्म के मारे, नाबालिग लड़की पूरी रात डेमुल में ही रही और अगली सुबह मेन रोड पर आ गई, जहाँ उसके परिवार ने उसे ढूँढ लिया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर, लेफ़ोपाड़ा पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की धारा 376(2) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेज्शुअल ऑफेंस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अरुण कालेत को

शुरू में 12 जनवरी, 2016 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, उसे 3 जनवरी, 2020 को जमानत मिल गई, जिसके बाद वह फरार हो गया। कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद, पुलिस ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया। आरोपी को 3 दिसंबर, 2024 को फिर से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जिससे ट्रायल खत्म हुआ। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिज्यूटर प्रभात कुमार नंदा ने राज्य की तरफ से केस को जल्दी खत्म किया। इंसाफ दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज् अथॉरिटी को पीड़ित को ₹5 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

पीआरसीआई राउरकेला अध्याय और प्रबंधन संघ राउरकेला द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रणनीतिक संकट प्रबंधन पर संगोष्ठी

राउरकेला ०५/०३ (संवाददाता): राउरकेला जलब में मैनेजमेंट एसोसिएशन राउरकेला (एमएआर) के सहयोग से भारतीय जनसंपर्क परिषद (पीआरसीआई), राउरकेला अध्याय द्वारा 'रणनीतिक संकट प्रबंधन' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक (खान विकास एवं सीएमएलओ), श्री बी के गिरि, समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीआरसीआई, श्रीमती गीता शंकर और आरएसपी के पुरस्कार विजेता लेखक एवं पूर्व संचार मुख्य, श्री रामेंद्र कुमार संगोष्ठी के सत्रमार्ग अतिथि थे। राज्य प्रमुख, पीआरसीआई, ओडिशा, डॉ. अशोक कुमार पंडा, मुख्य महाप्रबंधक (अपवर्तक) और सचिव, एमएआर, श्री एस एस पंडा एवं

महाप्रबंधक (जनसंपर्क) एवं संचार मुख्य, आरएसपी और अध्यक्ष, पीआरसीआई, राउरकेला अध्याय, सुश्री अर्चना शतपथी भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर पीआरसीआई, राउरकेला चैप्टर और एमएआर के बड़ी संख्या में सदस्य, क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि के साथ-साथ संकाय सदस्य और मास कज्जुनिकेशन के छात्र उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री गिरि ने आज के गतिशील और डिजिटल रूप से जुड़े वातावरण में प्रभावी संकट को तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की। भगवद गीता के काव्यात्मक हिंदी छंदों और श्लोकों के साथ, उन्होंने संकट के समय में कर्तव्य, लचीलापन और विचारों की स्पष्टता के



सिद्धांतों को स्पष्ट किया, प्राचीन ज्ञान और समकालीन नेतृत्व चुनौतियों के बीच समानताएं खींचीं। सुश्री गीता शंकर ने अपने संबोधन में प्रभावी संकट संचार की आधारशिला के रूप में विश्वास और विश्वसनीयता के महत्व के बारे में बात की, इस बात पर जोर दिया कि संगठनों को हितधारक विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार पारदर्शिता, जवाबदेही और

नैतिक आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए। श्री रामेंद्र कुमार ने अपनी विशिष्ट आकर्षक शैली में, संकट संचार में सहानुभूति के महत्व पर स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श किया, इस बात पर जोर दिया कि रणनीतियों और बयानों से परे, यह मानवीय संवेदनशीलता और समझ है जो वास्तव में विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करती है। उन्होंने एक घातक कैंसर के खिलाफ अपनी

व्यक्तिगत लड़ाई पर भी विस्तार से बताया, लचीलापन की अपनी यात्रा और प्रभावी संकट प्रबंधन के सिद्धांतों के बीच शक्तिशाली समानताएं खींचीं। डॉ. अशोक पंडा ने अपने परिचयात्मक संबोधन में, डिजिटल युग में संकटों की बढ़ती जटिलता और संरचित संचार ढांचे और नेतृत्व-संचालित प्रतिक्रिया तंत्र की अनिवार्यता को उजागर करके संगोष्ठी के लिए संदर्भ निर्धारित

किया। श्री एस एस पंडा ने सभा का स्वागत किया, और वर्तमान व्यापार और सामाजिक परिदृश्य में विषय की प्रासंगिकता को छुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों ने रामेंद्र कुमार द्वारा लिखित पुस्तक 'कैंसर से मुकाबला' का विमोचन किया, जिसमें बीमारी के खिलाफ उनकी साहसी संघर्ष का वर्णन है जो तन्यता, आशा और

सकारात्मक सोच की शक्ति पर प्रेरक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तकनीकी सत्र में, श्रीमती अर्चना शतपथी ने 'संकट के समय के दौरान विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण' पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें विभिन्न केस स्टडीज के साथ उन्होंने संगठनात्मक प्रतिष्ठा को संरक्षित करने में पारदर्शिता, सुसंगत संदेश और हितधारक जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला। इससे पहले, उप प्रबंधक (जनसंपर्क) और सचिव, पीआरसीआई, राउरकेला अध्याय, श्री सासांका एस. पटनायक ने 'डिजिटल अग्निशमन संकट से पहले, दौरान और बाद में सोशल मीडिया का प्रबंधन' पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें सक्रिय निगरानी, समय पर प्रतिक्रिया तंत्र और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में रणनीतिक

सामग्री प्रबंधन पर जोर दिया गया। प्रश्नोत्तरी जादूगर सहायक महाप्रबंधक (कोक ओवन), श्री संपद मिश्रा और वरिष्ठ प्रबंधक (एसईडी), श्री सौज्या रंजन बिस्वाल द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ज्ञान दीप के प्रकाश के साथ समारोह की शुरुआत हुई। निदेशक, पीआरसीआई राष्ट्रीय अध्याय, श्री जे जे दास और सहायक महाप्रबंधक (बागवानी- ज्यूरैटर और बायोलाॅजिस्ट), डॉ. सत्य नारायण मिश्रा ने क्रमशः दो सत्रों में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सुश्री शाहीन शेख ने सुबह के सत्र का समन्वय किया जबकि सुश्री प्रतिमा साहू ने कार्यक्रम के तकनीकी सत्र का समन्वय किया।